'डॉक्टर ऑफ द ईयर' से सम्मानित हुए प्रदेश के 25 डॉक्टर

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 07 | मूल्य 15 रुपये | 06-12 जुलाई, 2025

सेवा और सुशासन के चार साल बेमिसाल

SGRRU

SHRI GURU RAM RAI UNIVERSITY DEHRADUN, UTTARAKHAND

Recognized by UGC u/s 2(f)of UGC Act, 1956

Legacy of Excellence Since 1952

PROUD TO BE ACCREDITED BY

ICAR INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

NABH NABL DSIR RECOGNIZED SIRO

ADMISSIONS OPEN 2025-26

UPTO 30% SCHOLARSHIP ON TOTAL COURSE FEE + ADDITIONAL SCHOLARSHIP UPTO 100% ON ELIGIBILITY BASIS

SECURE YOUR SEAT NOW

ACADEMIC & RESEARCH EXCELLENCE IN

- Medical & Health Sciences
- Nursing
- Paramedical & Allied Health Sciences
- Basic & Applied Sciences
- Agricultural Sciences
- Pharmaceutical Science
- Engineering & Technology
- Humanities & Social Sciences
- Yogic Science & Naturopathy
- Management & Commerce Studies
- Education
- Hotel Management

100+ Laboratories

2000+ Research Publication

100+ Patents

70+ Years of Excellence

500+ Recruiters

1 Lakh+ Alumni

125+ Courses

Offering **NCC & NSS**

RANKED AMONG TOP UNIVERSITIES IN UTTARAKHAND

Toll Free Number **1800-120-102-102**

SCAN HERE TO REGISTER

admission@sgrru.ac.in   www.sgrru.ac.in   Patelnagar/Pathribagh, Dehradun

वर्ष 15 | अंक 07

दिव्य हिमगिरि

06-12 जुलाई, 2025

संपादक
कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

ब्यूरो प्रमुख
मोनिका डबराल

विज्ञापन
पूनम आर्या

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित। संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

किराया दुगुना सेवाएं आधी

शहरों-महानगरों में सार्वजनिक परिवहन की सीमाओं की वजह से आम आदमी आवश्यकता पड़ने पर ऐप आधारित कंपनियों के वाहनों से अपने गंतव्य तक आवाजाही कर लेता था। मगर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश लागू होने के बाद ऐसे वाहनों से सफर महंगा होने की स्थिति में अब लोगों को सोचना पड़ेगा। अव्वल तो व्यस्त समय को कारण बना कर समान दूरी तक सफर के लिए दोगुना किराया लेना अनुचित है, फिर यह बेहद निराशाजनक है कि पहले ही महंगाई के बोझ से दबे आम लोगों पर किराए की मार के साथ-साथ बुकिंग रद्द कर देने पर जुर्माना लगाने का नियम भी सख्त कर दिया गया है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। इससे यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा पाया गया है कि कैब कंपनियों की गाड़ियां समय पर नहीं आतीं। ऐसे में लोगों को विवश होकर अपनी बुकिंग रद्द करनी पड़ती है। वहीं चालकों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। वे कई बार यात्रा का डिजिटल भुगतान करने पर जोर देते हैं और पसंद का गंतव्य न मिलने पर खुद भी बुकिंग रद्द कर देते हैं। हालांकि अब ऐसे चालकों की नकेल कसने के लिए उन पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि राज्य सरकारों को नए दिशा-निर्देश लागू करने की सलाह के बाद आम लोगों पर ही इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। व्यस्त समय में किराया बढ़ाने का चलन नया नहीं है। मगर मूल्य निर्धारण का यह मनमाना तरीका आखिरकार यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता है। कैब सेवा प्रदाता कंपनियों को दोगुना किराया लेने की अनुमति देने से पहले यात्रियों की शिकायतें सुनने और उन्हें दूर करने की जरूरत थी। हाल में आए एक सर्वेक्षण में आधे से अधिक यात्रियों का कहना है कि इन कंपनियों की सेवाएं बेहतर नहीं हैं। कई बार तो गाड़ियों के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। वाहनों की साफ-सफाई और चालकों के खराब व्यवहार पर भी लोग प्राय: सवाल उठाते रहे हैं। अचानक किराया बढ़ा दिए जाने से लोग पहले ही परेशान थे। अब तो सीधे-सीधे लोगों की जेब से दोगुना किराया वसूलने की व्यवस्था थोप दी गई है। नए दिशा-निर्देश से आखिरकार आम लोगों को ही नुकसान होगा। दरअसल सरकार ने रिवाईज्ड मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 मे द्वारा उबर, ओला और रैपिडो जैसे कैब एग्रीगेटर्स को पीक अक्कवर्स के दौरान बेस फेयर से दो गुना तक किराया वसूलने की इजाजत दे दी है। इससे पहले, ये एग्रीगेटर्स पीक आवर्स के दौरान सर्ज प्राइस या डायनमिक फेयर के रूप में बेस फेयर का 1.5 गुना चार्ज कर सकते थे। अब सरकार ने कहा कि गैर-पीक घंटों के दौरान, एग्रीगेटर बेस किराए का न्यूनतम 50 प्रतिशत चार्ज कर सकते हैं। राज्यों को तीन महीने के अंदर नए दिशानिर्देश अपनाने की सलाह दी गई है।

कुँवर राज अस्थाना

अच्छी कंडीशन के वाहनों को भी कबाड़ बनाने की सरकारी नीति!

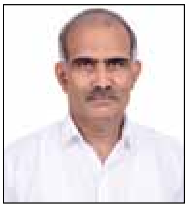

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

देश मे विमान तो दो दशक से भी अधिक पुराने चल रहे है लेकिन सड़क पर चलने वाले वाहन यदि डीजल के है तो अधिकतम 10 वर्ष और यदि पैट्रोल के है तो अधिकतम 15 साल ही चल सकते है, फिर चाहे उनकी कंडीशन कितनी भी अच्छी क्यो न हो, उन्हें कबाड़ में बेचना ही होगा। सरकार के इस निर्णय को लेकर देशभर के वाहन स्वामियों में आक्रोश व्याप्त है। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों को कबाड़ में बदलने के नियम के तहत उन्हें ईंधन न देने का तुगलकी फरमान जारी किया गया, जो 2 दिन बाद ही वापस लेना पड़ा। इस नियम के लागू होने से वाहन मालिकों ने गुस्सा दिखाया कि दिल्ली सरकार को 2 दिन में ही घुटने टेकने पड़े है, क्योंकि उन्हें अपनी अच्छी हालत वाली गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कार मालिक सवाल उठा रहे हैं कि जब उनकी गाड़ियां अच्छी स्थिति में हैं, तो उन्हें कबाड़ में क्यों बदला जा रहा है? वे भारत सरकार के इस फैसले पर हैरानी जता रहे हैं।

इस फैसले से पहले ही, कार मालिकों पर गाड़ियों के रखरखाव और टैक्स का बोझ है। अब उन्हें अपनी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे वाहन स्वामियों की परेशानी और बढ़ गई है। वाहन स्वामियों का कहना है कि सरकार का यह फैसला मनमाना है और इससे सार्वजनिक परिवहन की कमी जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि उनकी गाड़ियां अच्छी हालत में हैं और उन्हें प्रदूषण का कारण नहीं माना जा सकता। उनका सवाल है कि जब अन्य देशों में पुराने वाहनों को अनुमति है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है?

वाहन मालिक चाहते हैं कि सरकार इस नियम पर पुनर्विचार करे और उनकी परेशानियों को कम करने के लिए पुराने वाहनों को फिटनेस के बाद अनुमति दे। उनका सवाल है क्या मेहनत की कमाई से खरीदी गई गाड़ी सिर्फ इसलिए जब्त की जा सकती है क्योंकि वह 10 या फिर 15 साल पुरानी हो गई है?

आंकड़ों के अनुसार, अकेले दिल्ली में लगभग 62 लाख से अधिक गाड़ियाँ इस नीति के दायरे में आती हैं, जिनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से पूरी तरह चालू और प्रदूषण मानकों के अनुसार फिट है, फिर भी उम्र का हवाला देकर उन्हें कबाड़ माना जा रहा है। लोगो में यह आम धारणा बन रही है कि पर्यावरण के नाम पर जनता से उनकी अच्छी कंडीशन की गाड़ियां कबाड़ के भाव छीनी जा रही है, जबकि इसके पीछे की वास्तविक मंशा वाहन कंपनियों को नया व्यापार दिलाना और स्क्रैपिंग से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना है। सन 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के तहत दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीज़ल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियाँ सड़क पर नहीं चलने का फरमान जारी किया गया था। इसे लागू करते समय किसी गाड़ी की तकनीकी स्थिति या प्रदूषण स्तर की जांच नहीं की गई, बल्कि केवल 'उम्र' को आधार बनाया गया।

न्यायमूर्ति स्वातंत्र कुमार का विवादित अतीत

इस आदेश के खिलाफ कई वाहन मालिकों और जनप्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन कोई राहत वाहन स्वामियों को नही मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने इस नीति को लेकर कई अहम दलीलें प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि यह एक मनमाना निर्णय बताया है, जिसमें केवल वाहन की उम्र को देखते हुए उसे सड़कों से हटाया जा रहा है, जबकि उसकी फिटनेस, रखरखाव और प्रदूषण स्तर को नजरअंदाज किया जा रहा है।

यह तर्क उठता है कि यदि गाड़ी फिटनेस और प्रदूषण जाँच पास कर रही है, तो केवल उम्र के आधार पर उसे कबाड़ घोषित करना एक तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से अधूरी नीति ही कही जाएगी ।

इस नीति से सर्वाधिक लाभ वाहन निर्माता कंपनियों को हो रहा है, जिनकी नई गाड़ियों की बिक्री में अचानक तेज़ी देखी गई। साथ ही स्क्रैपिंग इंडस्ट्री, वाहन डीलरों और कुछ अफसरशाही तंत्र को भी इससे नया अवसर मिला, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हुए। दूसरी ओर, इसका बोझ मध्यम वर्गीय परिवारों, टैक्सी चालकों, सीमित आय वाले निजी वाहन मालिकों पर पड़ा, जिनके लिए हर 10 या 15 साल में नई गाड़ी खरीदना संभव नहीं है। यह नीति एक प्रकार से संपत्ति के हस्तांतरण की ऐसी व्यवस्था बनती जा रही है जिसमें मेहनतकश वर्ग से धन निकालकर धनाढय वर्ग को सौंपा जा रहा है।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 35 लाख से अधिक पेट्रोल व डीज़ल गाड़ियाँ बिकती हैं, यह नीति यदि वाकई पर्यावरण के हित में थी तो इसमें यह प्रावधान हो सकता था कि हर गाड़ी का तकनीकी परीक्षण हो, यदि वह फिटनेस और प्रदूषण जांच में सफल हो, तो उसे 5 वर्षों का विस्तार दिया जाए।

(लेखक ज्वलंत मुद्दों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार है)

सेवा और सुशासन के चार साल बेमिसाल

मिशन 2027 के लिए शीर्ष नेतृत्व ने सीएम धामी और महेंद्र भट्ट की जोड़ी पर लगाई "मुहर"

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड भाजपा में तीन दिन (1 से 4 जुलाई) 'रिकॉर्ड बने, परंपराएं टूटी और मिशन 2027' भी रेखांकित कर शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जोड़ी पर भरोसा कायम रखा। वहीं सीएम धामी और महेंद्र भट्ट के चेहरे की मुस्कान, आत्मविश्वास बता गया कि हाईकमान ने उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए हरी झंडी दे दी है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। 4 जुलाई को सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए। वे राज्य के एकमात्र नेता हैं, जिन्हें राज्य के गठन के बाद से लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। वह पहले भाजपा नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर चार वर्ष पूरे किये। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जनता का आभार जताया।

उत्तराखंड भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से छोटा राज्य है। आमतौर पर यहां राजनीतिक हलचलें कम देखने को मिलती है। लेकिन यह भी सही है उत्तराखंड की शांत राजनीति में जब-जब गर्माहट आती है तो इसकी धमक दिल्ली तक पहुंचती रही है। उत्तराखंड भाजपा में तीन दिन (1 से 4 जुलाई) 'रिकॉर्ड बने, परंपराएं टूटी और मिशन 2027' भी रेखांकित कर शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जोड़ी पर अंतिम मुहर लगा दी। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं से भरी है, कब और क्या नया होने वाला है सियासत के जानकार भी नहीं समझ पाए। मुख्यमंत्री धामी और महेंद्र भट्ट के चेहरे की मुस्कान, आत्मविश्वास बता गया कि हाईकमान (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) ने उन्हें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए हरी झंडी दे दी है। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी अपना पूरा कार्यकाल (सीएम के रूप में एनडी तिवारी को छोड़कर) नहीं कर पाए हैं। भाजपा आलाकमान ने महेंद्र भट्ट को पिछले साल अप्रैल 2024 में राज्यसभा सांसद बनाया था तभी से उनके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ने की अटकलें चल रही थी। (भाजपा की गाइडलाइन के अनुसार एक व्यक्ति दो पदों पर नहीं रह सकता।) लेकिन पार्टी नेतृत्व ने भट्ट पर एक बार फिर भरोसा जताया और अपने मिथक को तोड़ते हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी। उत्तराखंड में पार्टी

की कमान किसको मिलेगी कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। सियासी बाजार में चर्चा थी कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई नया चेहरा सामने लाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट मंगलवार (1 जुलाई, 2025) को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। वे राज्य में भाजपा के एकमात्र नेता हैं, जिन्होंने राज्य के गठन के बाद से लगातार दो बार इस पद को संभाला है। हालांकि, उनकी जीत पहले से तय थी, क्योंकि वे इस पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। उत्तराखंड में ठाकुर मुख्यमंत्री और ब्राह्मण अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। उत्तराखंड बीजेपी की दोबारा कमान मिलने पर महेंद्र भट्ट ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और साल 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कमर कस ली है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। शुक्रवार, 4 जुलाई को सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने भी सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश की जनता का आभार जताया। 4 साल पहले 4 जुलाई साल 2021 को पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, धामी को 2021 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राज्य के 25 साल के अस्तित्व में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। मुख्यमंत्री धामी ने अपने दोनों कार्यकाल को मिलाकर 4 साल पूरी किए हैं। भाजपा ने राज्य में चले आ रहे कई मिथक और धारण ाा को तोड़ा है। साल 2022 के फरवरी महीने में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चुनावी हार के बाद शीर्ष नेतृत्व ने कमान उनके हाथ से वापस नहीं ली। कहीं न कहीं धामी पार्टी हाई कमान की कसौटी पर खरे साबित हुए हैं। सीएम धामी से पहले कांग्रेस के नरेंद्र तिवारी ही लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। यह रिकॉर्ड अभी भी दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज पंडित नारायण दत्त तिवारी के नाम है, जिन्होंने पूरे पांच साल का कार्यकाल पूरा

सीएम धामी ने हुडके की थाप पर खटीमा में की धान रोपाई

किसानों के श्रम को किया नमन

खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत 'हुड़किया बौल' के माध्यम से भूमि के देवता भूमियां, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। मुख्यमंत्री के इस सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री धामी की यह पहल उत्तराखंड की ग्रामीण संस्कृति, कृषकों की अहमियत और पारंपरिक लोककलाओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है।

किया था। 4 साल के कार्यकाल में सीएम धामी की उपलब्धि का श्रेय उनके नेतृत्व में लिए गए दर्जनों जन-कल्याणकारी निर्णयों को दिया, जिनमें कठोर नकल विरोधी कानून, भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए उनके चार साल की यात्रा सुखद है। मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व ने मिलकर 2027 में विधानसभा के चुनाव का खाका भी तैयार कर लिया है। सरकार की योजनाओं और कामकाज को लेकर विपक्ष भी उतना आक्रामक नहीं दिखता है जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मजबूती के साथ सरकार चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

सीएम धामी ने अपने 4 साल के कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे और मां गंगा का पूजन किया। अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर भी अपनी उपलब्धियों का बखान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाइयों-बहनों, जहां इन 4 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, सख्त धर्मांतरण कानून, दंगारोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया है वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों व अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई और सख्त भू-कानून लागू कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा हेतु अपनी प्रतिबद्धता को साबित किया है। इन 4 वर्षों में एक ओर जहां प्रदेश सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश का अग्रणी राज्य बना है वहीं दूसरी ओर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए इकोलॉजी, इकॉनमी और टेक्नोलॉजी के बेहतर समन्वय से रोड, रेल और रोपवे निर्माण के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। सीएम हेल्पलाइन 1905 और 1064 विजिलेंस ऐप से सदैव आम जनमानस के विश्वास को जीतने का प्रयास किया है और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मगरमच्छ जैसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजकर एक सख्त संदेश भी दिया। युवा साथियों को इन 4 वर्षों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ 23000 से भी अधिक सरकारी नौकरी दी है और महिलाओं को 30: क्षैतिज आरक्षण देकर उनकी सशक्त भागीदारी भी सुनिश्चित की है। यही कारण है कि आज प्रदेश में बेरोजगारी दर तेजी से घटी है जो कि राष्ट्रीय औसत से भी कम है। धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के फलस्वरुप प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा एवं कांवड़ यात्रा में देवभूमि उत्तराखंड पधार रहे हैं। आपके आशीर्वाद और आदरण ीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के पुनर्विकास, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय उत्पादों का बढ़ चढ़कर प्रचार-प्रसार, होम स्टे योजना के माध्यम से स्वरोजगार, छात्रवृत्ति योजनाएँ, खेल और खिलाड़ियों के लिये बेहतर सुविधाएं, किसान कल्याण, सैनिक कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य आज देवभूमि उत्तराखंड के विकास का नया अध्याय लिख रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देते हुए रिकॉर्ड 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए और अभी तक 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगामी वर्षों में देवभूमि उन्नति और प्रगति के क्षेत्र में नये सोपान गढ़ने को तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए देवतुल्य जनता और केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार। उत्तराखंड में अब तक भाजपा के मुख्यमंत्रियों ऐसा रहा है कार्यकाल। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक। भगत सिंह कोश्यारी 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक। भुवन चंद खंडूरी 7 मार्च 2007 से 26 जून 2009 तक। रमेश पोखरियाल निशंक 27 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक। भुवन चंद खंडूरी 11 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक। त्रिवेंद्र सिंह रावत 18 मार्च 2017 से 10 मार्च 2021 तक। तीरथ सिंह रावत 10 मार्च 2021 से 3 जुलाई 2021 तक। पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2021 से जारी है।

महेंद्र भट्ट की उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष पद पर दुबारा ताजपोशी

भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने महेंद्र भट्ट को 2022 में उत्तराखंड भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। उन्हें एक बार फिर भाजपा ने अध्यक्ष बनाया है। भट्ट दो बार के विधायक हैं और एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उत्तराखंड भाजपा संगठन प्रदेश अध्यक्ष का मुखिया इसलिए बनाया गया क्योंकि इसके पीछे निकाय चुनावों में पार्टी की बंपर जीत, विधानसभा चुनाव में दोबारा से बीजेपी की जीत, पूर्व में त्रिस्तरीय पंचायत में बीजेपी की जीत, इसके अलावा लोकसभा चुनाव में पांचों सीटे बीजेपी की जीत। यह सभी चुनाव ऐसे थे जिसमें भाजपा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर महेंद्र भट्ट ने पार्टी संगठन को बंपर जीत दिलवाई है और यही वजह है कि एक बार फिर से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। चमोली के मूल निवासी और नंदप्रयाग और बद्रीनाथ से दो बार विधायक रहे भट्ट ने कहा कि वह राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने सबसे पहले 2022 में मदन कौशिक की जगह उत्तराखंड में भाजपा के अध्यक्ष का पद संभाला था। राजनीतिक पर्यवेक्षक भट्ट को भाजपा के उत्तराखंड अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने को पार्टी के ब्राह्मण वोट बैंक को खुश करने के फैसले के रूप में देखते हैं, जो लंबे समय से पार्टी के मुख्यमंत्रियों की पसंद पर आपत्ति जताते रहे हैं। 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से राज्य में तीन मुख्यमंत्री हुए हैं, वे सभी ठाकुर हैं। इस बार भी भगवा पार्टी ने ठाकुर समुदाय से मुख्यमंत्री और ब्राह्मण समुदाय से राज्य इकाई का अध्यक्ष चुना है, ताकि राज्य में आधे से ज्यादा मतदाता इन दो समुदायों को खुश कर सकें।

दिव्य हिमगिरि ने किया दून मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन

'डॉक्टर ऑफ द ईयर' से सम्मानित हुए प्रदेश के 25 डॉक्टर

स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों के लिए की 05 बड़ी घोषणाएं

प्रदेश के 11 मेडिकल कॉलेजों की भागीदारी से सम्पन्न हुआ सम्मान समारोह

नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित 'डॉक्टर ऑफ द ईयर' सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार इसी वर्ष से 'डॉक्टर ऑफ द ईयर' की तर्ज पर मेडिकल फैकल्टी के लिए 05 चरक अवार्ड और उत्कृष्ट डॉक्टर के लिए 05 सुश्रुत अवार्ड प्रारंभ करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अवार्ड के लिए राज्य सरकार 1,00,000/-, 75000/- और 50000/- और 25-25 हजार रुपए की धनराशि भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही जिन डॉक्टर को और मेडिकल फैकल्टी को यह अवार्ड प्राप्त होगा उनको ट्रांसफर के मामले में 2 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी और साथ ही एक वर्ष के लिए अध्ययन हेतु विदेश भेजने की व्यवस्था करने की घोषणा की।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर गर्वनमेंट दून मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में दिव्य हिमगिरि, उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में 'डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड-2025' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि पद्म श्री डॉ. बी. के. एस. संजय एवं अध्यक्ष डॉ. ओंकार सिंह थे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण त्रिपाठी, चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना तथा दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन भी मंचासीन थे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि 2025 के अंत तक सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सभी पदों में नियुक्ति हो जाएगी। साथ ही पदोन्नति को भी शत प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक अलग से काडर बनाया जाएगा तथा पर्वतीय भत्ता 50 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष के अंत तक सभी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल फैकल्टी के लिए शत प्रतिशत आवास बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने चिकित्सकों तथा मेडिकल फैकल्टी के ट्रांसफर के लिए अलग से ट्रांसफर नीति लाने की घोषणा भी की, जिसमें एक व्यक्ति एक पद पर एक जगह 03 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पूरे प्रदेश से चयनित 25 उत्कृष्ट डॉक्टर को इस वर्ष का 'डॉक्टर ऑफ द ईयर' अवार्ड प्रदान किया।

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्म श्री डॉ. बी. के. एस. संजय ने कहा कि आज सड़क दुर्घटनाएं विकलांगता का मुख्य कारण है। सड़क दुर्घटनाओं ने प्रदेश में तबाही मचा रखी है। हर साल लगभग 1500 दुर्घटनाएं होती है जिनमें 1000 लोगों की मौत हो जाती है। डॉ. संजय ने मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत जी से अनुरोध किया कि सड़क सुरक्षा स्कूली शिक्षा के पाठयक्रम का हिस्सा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल प्रदेश बल्कि देश के हित में ऐतिहासिक कदम होगा।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. ओंकार सिंह ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना

व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए कि समाज का एक तबका इसका लाभ ही ना ले सके। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण त्रिपाठी ने स्वस्थ जीवन एवं सफल इलाज में आयुष चिकित्सा के महत्व को रेखांकित किया। चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखंड के निदेशक, डॉ. आशुतोष सयाना ने कहा कि चिकित्सकों को कुछ हद तक निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए और समाज को उनके सेवा भाव की सराहना करनी चाहिए। कार्यक्रम को दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. गीता जैन ने भी संबोधित किया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के अन्य अतिथियों ने भी चिकित्सकों के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम का स्वागत संबोधन आयोजन सचिव एवं दिव्य हिमगिरि के संपादक कुँवर राज अस्थाना ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉ. आशीष उनियाल ने दिया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने. डॉ ऋचा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

जिनको सम्मानित किया गया

1. डॉ. अनुराग रावत, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
2. डॉ. जयंती सेमवाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
3. डॉ. गुरजीत खुराना, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जॉलीग्रांट
4. प्रो. (डॉ.) चंद्र शेखर, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार
5. डॉ. ओमना चावला, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार
6. डॉ. डी.के. टम्टा, वीसीएसजी राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (गढ़वाल)
7. डॉ. दीपा हटवाल, वीसीएसजी सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर (गढ़वाल)
8. प्रो. (डॉ.) वरुण कुमार, सीमा डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, ऋषिकेश
9. डॉ अंजुम सैयद, एम्स ऋषिकेश
10. डॉ. शैलेन्द्र हांडू, एम्स ऋषिकेश
11. डॉ. मोहित ढींगरा, एम्स ऋषिकेश
12. डॉ. अजय कुमार गुप्ता, ऋषिकुल परिसर, यूएयू, हरिद्वार
13. डॉ. ज्ञानेंद्र दत्त शुक्ल, गुरुकुल परिसर, यूएयू, हरिद्वार
14. डॉ. मन्नत मरवाहा, हर्रावाला कैम्पस, यूएयू, देहरादून
15. डॉ. (लेफ्टिनेंट कर्नल) राहुल शुक्ला, गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय
16. डॉ. (श्रीमती) सविता गोयल, सविता पैथोलॉजी सेंटर
17. डॉ. पंकज अरोड़ा, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज
18. डॉ तृप्ति ममगाई, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज
19. डॉ. उत्कर्ष शर्मा, श्री महंत इंद्रेश अस्पताल और एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज
20. डॉ. अखिलेश पांडे, ग्राफिक एरा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंस
21. डॉ. उषा रावत, राजकीय अल्मोडा मेडिकल कॉलेज
22. डॉ. अशोक कुमार, राजकीय अल्मोडा मेडिकल कॉलेज
23. डॉ. अभय, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून
24. डॉ. वंदना बिष्ट, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून
25. डॉ शिव यादव, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून

1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित चिकित्सकों के सम्मान समारोह के समापन पर प्रदेश के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का दिव्य हिमगिरि की ओर से जताया आभार

भारतीय रेलवे ने 'रेल वन ऐप' से यात्रियों का सफर बनाया स्मार्ट

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को और आसान बनाने की दिशा में 1 जुलाई को रेल वन ऐप लान्च किया है। यह एप यात्रियों को सभी प्रकार की रेल टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन की लाइव ट्रैकिंग, शिकायत दर्ज करने और खाने के आर्डर तक की सभी सेवाएं एक ही प्लेटफार्म पर प्रदान हो रही है। रेलवे का यह प्रयास यात्रियों को बार-बार अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने या वेबसाइट पर जाने की परेशानी से राहत दिलाएगा। यह एप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ डिजाइन किया गया है और हिंदी व अंग्रेजी समेत कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यात्रियों को उनकी सुविधा अनुसार भाषा चुनने का विकल्प भी मिलेगा। अभी तक आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट व ऐप के माध्यम से टिकट बुक करते थे, लेकिन इस ऐप में आइआरसीटीसी को भी मर्ज कर दिया गया है। यानि अब एक ही ऐप में सभी सुविधा मिलेगी। दिव्य हिमगिरि की विशेष रिपोर्ट।

एक जुलाई से भारतीय रेलवे ने कई बदलाव किए। यह बदलाव सीधे ही यात्रियों से जुड़े रहे। हालांकि रेलवे ने 5 साल बाद ट्रेन किराए में मामूली बढ़ोतरी भी की। इंडियन रेलवे का नया ऐप 'रेल वन' इन दिनों चर्चा में है। यह एक ऐसा ऐप है जिसने यात्रियों का सफर स्मार्ट और आसान बना दिया है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। रोजाना लाखों-करोड़ों लोग रेल से सफर करते हैं। वहीं रेलवे भी समय समय पर अपने यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कई नई ऐप और सर्विस लॉन्च करती रहती है। अब रेलवे ने यात्रियों को और भी बेहतर सुविधा देने के लिए एक नई ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम रेलवन है। यह रेलवे की सुपर ऐप है, जिसे 1 जुलाई को भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को रेल वन नाम से यह ऐप पेश किया। ऐप के जरिए यात्री रिजर्व टिकट, अनरिजर्व या जनरल टिकट, प्लेटफार्म टिकट, मंथली सीजन टिकट जैसे सभी टिकट बुक कर सकते हैं। साथ में पीएनआर भी चेक कर सकते है। यह ऐप ट्रेन के रनिंग स्टेटस को भी बताएगी। इस ऐप के जरिए आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं रेलवे की किसी भी तरह की शिकायत भी आप इस ऐप के जरिए ही कर सकते हैं। आप इस ऐप के जरिए रिजर्व टिकट के लिए टीडीआर भी फाइल कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे के लिए एक नई सुपर ऐप पर तैयारी काफी समय से चल रही थी, जिसके बाद अब यह नई ऐप लॉन्च की गई। यह नई ऐप यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक है। एप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल एप स्टोर से इसे डाउनलोड करें। ऐप इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होगा। फिर एमपिन सेट करें या बायोमेट्रिक लॉगिन एक्टिव करें। एक बार लॉगिन हो जाने के बाद टिकट बुकिंग, लाइव स्टेटस, शिकायत जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि ये सभी बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान करने के लिए किए गए हैं। रेलवे लगातार नई तकनीकों और सुविधाओं पर काम कर रहा है, ताकि यात्रियों को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिले। मंत्रालय के मुताबिक, भविष्य में और भी सुधार किए जाएंगे, जिनमें स्टेशनों का आधुनिकीकरण और ट्रेनों की गति बढ़ाने जैसे कदम शामिल हैं।

भारतीय रेलवे ने एक जुलाई से किए कई बदलाव

भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई से कई बदलाव किए इन बदलावों में टिकट की कीमतों व फेरबदल शामिल हैं। रेलवे ने लंबे समय बाद टिकट की कीमतों में बदलाव किया है। नॉन-एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जबकि एसी क्लास में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर है। हालांकि, 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए सेकंड क्लास टिकट और मासिक सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना होगा। रेलवे का कहना है कि यह बढ़ोतरी पिछले पांच सालों में की गई पहली बदलाव है और इसे यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी बताया गया है। तत्काल टिकट बुक करने वालों के लिए रेलवे ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। बुकिंग के दौरान आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके बिना टिकट

बुक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा, रेलवे एजेंटों के लिए भी नया नियम लागू किया गया है। अब एजेंट तत्काल बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। रेलवे का कहना है कि यह कदम टिकट बुकिंग को पारदर्शी बनाने और कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने का समय भी बदल दिया है। पहले यह चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से चार घंटे पहले बनता था, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने में मुश्किल होती थी। नए नियम के तहत यात्रियों को अपनी टिकट की स्थिति जानने के लिए 8 घंटे पहले जानकारी मिल जाएगी, जिससे वे अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। रेलवे ने इस बदलाव को लागू करने से पहले बीकानेर डिवीजन में एक ट्रायल भी किया था, जिसमें यात्रियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। वहीं वेटिंग टिकट वाले यात्रियों के लिए भी रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा। इसका मतलब है कि स्लीपर या एसी कोच में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यह नियम पहले मई 2025 से लागू किया गया था, और अब इसे और सख्ती से लागू किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इस बदलाव से कन्फर्म टिकट वालों को ज्यादा सुविधा मिलेगी और कोच में भीड़ कम होगी।

कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को लिखना होगा नाम

उत्तराखंड में इसी महीने 11 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य दुकानों पर फूड लाइसेंस और विक्रेता का नाम लिखना होगा। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि प्रदेश में थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। सीएम धामी ने कहा कि बीते कुछ समय से भोजन और खाद्य पदार्थों को इस तरह अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले भी इस मामले में कठोर कार्रवाई की है आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिये 'उत्तराखण्ड कांवड़ सेवा एप' बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एप में कांवड़ियों की सभी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। दिव्य हिमगिरि की रिपोर्ट।

11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार दोनों प्रदेशों की सरकार ने यात्रा को लेकर दुकानदारों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान इस साल भी खाद्य दुकानों पर फूड लाइसेंस और विक्रेता का नाम लिखना होगा। यूपी के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं। सभी खाद्य दुकानों पर अनिवार्य रूप से दुकानदार को फूड लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार के निर्देशों का पालन करने पर दुकानदार पर जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि प्रदेश में थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। सीएम धामी ने कहा कि बीते कुछ समय से प्रदेश में थूक जिहाद जैसी घटनाएं सामने आई है। भोजन और खाद्य पदार्थों को इस तरह अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने पहले भी इस मामले में कठोर कार्रवाई की है आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आयुक्त एफडीए डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कांवड़ यात्रा

मार्ग के लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोरी रोकने के लिए अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। छोटे व्यापारियों में ठेले-फड़ वालों को भी फूड लाइसेंस पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदेश करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही कावड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों के साथ-साथ दुकानदारों में परोसे जा रहे हैं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर 18001804246 जारी किया गया है। इस नंबर पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज किया जा सकती है। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ आर. राजेश कुमार ने कहा कि जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें 2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन हो। श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

कांवड़ियों की सभी जानकारी के लिए 'उत्तराखण्ड कांवड़ सेवा एप' बनेगा

इसी महीने 11 जुलाई से उत्तराखंड में शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर धामी सरकार ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मेला नियंत्रण भवन हरिद्वार में उच्चाधिकारियों के साथ कांवड़ मेला की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिये 'उत्तराखण्ड कांवड़ सेवा एप' बनाए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एप में कांवड़ियों की सभी डिटेल उपलब्ध कराई जाए। इस एप का उपयोग हर वर्ष आयोजित होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान किया जा सकेगा, इस से कांवड़ यात्रा पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के सकुशल एवं सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रशासन, पुलिस एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे राज्य जहां से अधिकांश कांवड़िए आते हैं। उन राज्यों से परस्पर समन्वय, रियल टाइम डाटा शेयरिंग और सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी आवश्यक इनपुट्स साझा किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को आगामी कुंभ मेले का ट्रायल बताते हुए कहा कि ये अनुभव आगामी कुंभ मेले भी काम आएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा मार्गो पर किसी भी तरह का अतिक्रमण न हो। उन्होंने कावड़ यात्रा से पहले सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन कराने के साथ ही फूड लाइसेंस और रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से चस्पा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्ग पर स्थित होटलों के नाम व होटल स्वामियों के नाम भी अनिवार्य रूप से लिखे हों एवं ओवर रेटिंग की शिकायत आने पर संबंधित होटल स्वामियों पर सख्ती से करवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान शराब तथा मांस से संबंधित एसओपी का भी सख्ती से पालन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमने क्लीन और ग्रीन कांवड़ यात्रा का संदेश देना है, स्वच्छता हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिसके लिए संपूर्ण कांवड़ मार्गो पर हर घंटे सफाई अभियान चलता रहे। हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और आस पास के क्षेत्रों में हर 1-2 किलोमीटर पर मोबाइल टॉयलेट, कूड़ा निस्तारण के लिए विशेष गाड़ियों की तैनाती की जाए। उन्होंने कहा कि कांवड़ रूट पर हर 2 से 3 किलोमीटर के अंदर स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएं, जिससे आम जन को सहूलियत हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कावड़ियों की सुविधा को देखते हुए स्थानीय निकायों के सहयोग से रैन बसेरों, टेंट सिटी, आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीवी और ड्रोन से नियमित निगरानी हो। कांवड़ रूट का जीआईएस मैपिंग आधारित ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए और ए.आई आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआर एफ, एनडीआरएफ की तैनाती, बारिश और भूस्खलन की पूर्व चेतावनी प्रणाली सक्रिय की जाए। साथ ही संवेदनशील घाटों पर एनाउंसमेंट सिस्टम भी मजबूत किया जाए।

हर्षल फाउंडेशन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

हर्षल फाउंडेशन ने आइएमएस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर आई एम एस यूनिसन यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया।

संस्था की ट्रस्टी सेक्रेटरी रमा गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया।

इस अवसर पर हर्षल फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक जस्टिस राजेश टण्डन, संरक्षक मेजर जनरल शम्मी सब्बरवाल, ब्रिगेडियर के जी बहल, पूर्व राज्यमंत्री राज कुमार पुरोहित जी ने संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्यो की बहुत प्रसंसा की। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। चंद्र वीर गायत्री, प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष अनुपम शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रेश गोयल, संयोजक सिंधु गुप्ता, निधि गर्ग आदि सदस्य उपस्थित रहें।

आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ अनिल सुब्बाराव, रजिस्ट्रार कर्नल सर, प्रशासनिक अधिकारी समीर जखमोला जी अपनी पूरी टीम के साथ रहे और कैम्प में पूरा सहयोग किया साथ ही स्वयं भी रक्तदान किया।

इस कैम्प की एक विशेषता रहीं कि सभी फैकल्टी, स्टाफ और भी यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। रक्तदान के लिए महंत इंद्रेश हॉस्पिटल की टीम आई थी। टोटल 61 यूनिट रक्त इस कैम्प के माध्यम से एकत्र किया गया। सभी रक्त दाताओं और आइएमएस यूनिसन यूनिवर्सिटी के पूरे स्टाफ का हर्षल फाउंडेशन शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इस कैम्प को सफ़ल बनाने में पूरा सहयोग किया।

उत्तराखंड के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में प्रदेश के भीतर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रदेश के अंतर्गत एनएच पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई की सड़कों की स्थिति और प्रगति की विस्तार से जानकारी ली।

मुख्य सचिव ने एनएच पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बॉटल नेक की जानकारी लेते हुए उन्हें दुरुस्त किए जाने के लिए शीघ्र योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन एवं वन्यजीव संस्तुतियों के लिए लगातार केन्द्र एवं राज्य स्तरीय सम्बन्धित विभागों से अनुवर्तन करते रहने की बात भी कही। कहा कि एनएच पीडब्ल्यूडी द्वारा लम्बित मामलों में सम्बन्धित जिलाधिकारियों और फारेस्ट के साथ लगातार बैठकें आयोजित करते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।

मुख्य सचिव ने ऋषिकेश बाईपास में बायपास को ऋषिकेश से शिवपुरी तक बढ़ाए जाने हेतु कार्यवाही शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र के स्तर से प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों के लिए लगातार प्रयास किए जाएँ। उन्होंने कलियासौड़ रिअलाइनमेंट और जोशीमठ बाईपास रिअलाइनमेंट कार्य पूर्ण किए जाने के लिए टाईमलाइन निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाने के लिए लगातार उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कार्यों को समय से पूरा किए जाने के लिए जिन कार्यों को समानान्तर शुरू किया जा सकता है, उन्हें शुरू कर लिया जाए।

मुख्य सचिव ने एनएचएआई के अंतर्गत बन रही सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने एनएचएआई के बल्लुपुर पोंवटा साहिब पैकेज 1 और 2, झाझरा-आशारोड़ी 4 लेन, हरिद्वार बायपास सहित विभिन्न स्तरों पर चल रहे प्रोजेक्टों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कार्यों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत पूर्ण किए जाएं।

सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 3589.99 किमी है, जो एनएच पीडब्ल्यूडी के पास 2028.19 किमी, बीआरओ के पास 986.8 किमी, एनएचआईडीसीएल के पास 130 किमी और एनएचएआई के पास 445 किमी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग के कुल 53 कार्य होने हैं, जिनमें से 47 को स्वीकृति प्राप्त है। 42 कार्य अवार्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 30 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 12 कार्यों पर कार्य गतिमान है। 5 कार्य अवार्ड होने बाकी हैं और 6 कार्य स्वीकृत होने बाकी हैं।

इस अवसर पर अपर सचिव श्री विनीत कुमार एवं रीजनल ऑफिसर एनएचएआई श्री विशाल गुप्ता एवं पीडी एनएचएआई श्री पंकज भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास पर पहुंच कर उनसे मुलाक़ात की। इस दौरान उनके मध्य विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से मंगलवार को राजभवन में पर्यटन सचिव श्री धीराज सिंह गर्ब्याल ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने उनसे चारधाम यात्रा एवं पर्यटन विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

भारत ने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी का पता लगाया: डॉ. वी नारायण

हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अन्तरिक्ष सम्मेलन 2025 का देहरादून में आयोजन

स्पेस मीट का आयोजन यूसैक के निदेशक प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत की पहल पर किया गया

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग अन्तरिक्ष सम्मेलन 2025 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर इसरो अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर देश भर से आए वैज्ञानिकों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'विकसित भारत/2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान तक सीमित न रहकर संचार, कृषि, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भारतीय वैज्ञानिक श्री शुभांशु शुक्ला द्वारा तिरंगा फहराने पर इसरो समेत समस्त वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुभांशु शुक्ला का मिशन गगनयान व भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चंपावत को मॉडल जिला बनाने के लिए इसरो और यूकास्ट द्वारा विकसित डैशबोर्ड का शुभारंभ किया तथा इसरो द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्पित है और प्रदेश में साइंस सिटी, साइंस एवं इनोवेशन सेंटर, एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन व अन्य अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन उत्तराखंड को 'स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टेट' बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रदेश के सतत विकास में सहयोगी सिद्ध होगा।

इसरो चेयरमैन डॉ. वी नारायणन ने कहा कि 1963 में भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया था। 1963 से अब तक भारत ने 100 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए हैं। 1975 तक हमारे पास अपने कोई सेटेलाइट नहीं थे, लेकिन अब भारत के पास अपने 131 सैटेलाइट हैं। टीवी ब्रॉडकास्ट से लेकर हर जगह सैटेलाइट बड़े पैमाने पर मददगार साबित हो रहे हैं। इसरो द्वारा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम पर कार्य किया जा रहा है। उस रॉकेट पर कार्य किये जा रहे हैं, जो पृथ्वी की लोवर ऑर्बिट पर 75 हजार किलो तक के सेटेलाइट को लॉन्च करेगा, जिसे करीब 27 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

इसरो चेयरमैन ने कहा कि एक समय था जब हमारे रॉकेट साइकिल से ले जाए करते थे, पर आज भारत ने कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर पानी के अणु की मौजूदगी का पता से लगाया है। भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार लैंड किया है। भारत, आदित्य एल-1 मिशन के साथ सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत ने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था और मंगल ग्रह की कक्षा में उपग्रह भेजने वाला चौथा देश है। हमारा लक्ष्य 2030 तक अपना स्पेस स्टेशन बनाने एवं 2040 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत अवश्य बनेगा। निदेशक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा कि आज हमारे जीवन में हर समय अंतरिक्ष डाटा का प्रयोग हो रहा है। अंतरिक्ष में सेटेलाइट हमें जीपीएस नेविगेशन के साथ कई तरह के अपडेट देते हैं। उत्तराखंड में हमने पशुधन का डाटा ऑनलाइन किया था। ऋषिगंगा, चमोली आपदा के दौरान हमने सेटेलाइट के माध्यम से मेपिंग की और डेटा तैयार किया, जिसका प्रयोग बाद में राष्ट्रीय नीति में भी किया गया। पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट में इस डाटा का इस्तेमाल किया गया। अर्थ ऑब्जर्वेशन, सेटेलाइट संवाद एवं सेटेलाइट नेविगेशन ने पूरी तरह से हमारे जीवन को बदलने का काम किया है। उत्तराखंड में आपदाओं के दौरान मैपिंग, वन संरक्षण एवं वनाग्नि की मैपिंग के क्षेत्र में सेटेलाइट डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

दवाएं नकली नहीं, तकनीकी कमियों से सैंपल हुए फेल

प्रदेश बन रहा फार्मा हब, विस्तार में जुटी हैं फार्मा कंपनियां, गुणवत्तापूर्ण दवाओं का हो रहा निर्माण:- प्रमोद कालानी

उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने की हो रही कोशिश

ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने प्रदेश तेजी से फार्मा हब बनने की दिशा में बढ़ रहा है। प्रदेश में फार्मा कंपनियों का विस्तार हो रहा है और यहां से निर्मित दवाएं विश्व के अनेक देशों में निर्यात की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के फार्मा हब बनने की दिशा में कुछ बाहरी प्रदेशों के लोग अडंगा लगाने का प्रयास कर रहे हैं और यहां की कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नकली दवा निर्माताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक नकली दवाओं और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी (एनएसक्यू) ड्रग में अंतर होता है। एनएसक्यू दवाएं नकली नहीं होती है उनमें महज तकनीकी कमी होती है।

उत्तरांचल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने बताया कि प्रदेश में पूर्ण रूप से गुणवत्तापूर्ण दवाओं का निर्माण हो रहा है। फार्मा कंपनियां दवा उत्पादन के सभी निर्धारित मापदंडों का पालन कर रही है। उनके मुताबिक अच्छी दवाएं तय मानकों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के अनुसार बनाई जाती हैं। वहीं नकली दवाएं या तो घटिया सामग्री से बनती हैं, या उनकी जानकारी और लेबलिंग जानबूझकर गलत दी जाती है।

एनएसक्यू दवा नकली नहीं: एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने बताया कि हर एनएसक्यू दवा नकली नहीं होती। उन्होंने कहा कि कोई भी लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चरर नकली दवाएं नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि मीडिया एनएसक्यू में फेल दवा को नकली बताता है जो कि सही नहीं है। यह तकनीकी कमियों का मामला है। ऐसे में यदि मीडिया इस दवा को नकली बताए तो कंपनी और उसकी ब्रांडिंग पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एसोसिएशन के सदस्य पीके बंसल ने बताया कि अधिकांश दवाएं पीएच में अंतर होने, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में विलंब, डिसॉल्यूशन टेस्ट में बदलाव या लेबलिंग की गलती से होती है। यह दवा किसी भी तरह से मरीज के लिए हानिकारक नहीं होती है। बस इसमें तकनीकी कमी होती है।

क्लाईमेट का भी होता है असर: एसोसिएशन के महासचिव संजय सिकारिया के मुताबिक हाल में जिन दवाओं के 27 सैंपल फेल होने की बात है। वह भी इन मामूली तकनीक के आधार पर ही फेल किये गये हैं। हमें 28 दिन में हायर टेस्टिंग लैब में इसकी जांच करने की अपील करनी होती है। मुख्य टेस्टिंग लैब कोलकत्ता में है। यदि वहां से भी सैंपल फेल होता है तो ही दवा को सब स्टैंडर्ड या नकली बताया जा सकता है। एसोसिएशन के सदस्य रमेश जैन के मुताबिक क्लाइमेट चेंज का असर भी दवाओं पर होता है। उनके मुताबिक कश्मीर में अलग मौसम होता है और तटीय इलाकों में दूसरा तो नार्थ-ईस्ट में अलग। दवा एक ही होती है। कैमिस्ट यदि इसे धूप में रखेगा तो इसकी गुणवत्ता प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि दवाओं को ठंडी जगह और अंधेरे में रखने की सलाह दी जाती है लेकिन सभी कैमिस्ट इसका पालन नहीं करते।

एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कालानी ने मीडिया से अपील की कि एनएसक्यू दवाओं को नकली न कहा जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया महज सेंटर ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ही दवाओं को नकली बताकर समाचार प्रकाशित या चैनल पर दिखा देते हैं इससे कंपनी की छवि और ब्रांड पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जबकि मीडिया से यह उम्मीद की जाती है कि कोलकत्ता स्थिति सेंट्रल लेबोरिटी (सीडीएल) से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही सही समाचार प्रकाशित किया जाए। फार्मा कंपनी की दवाओं को एनएसक्यू के आधार पर नकली न करार दिया जाए। इससे कंपनी की ब्रांड और छवि खराब होती है। प्रदेश सरकार दे रही हरसंभव मदद।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

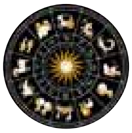
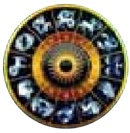

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बदलते माहौल की वजह से आपने अपने काम करने के तरीके में जो बदलाव किया है, वह फायदेमंद साबित होगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवा सोशल मीडिया में समय बिताने की वजह से आपके कुछ जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं।

वृषभ राशि- किसी भी परेशानी से घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें, इससे आप सही फैसला ले पाएंगे और जरूर सफलता मिलेगी। करीबी रिश्तेदारों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। संतान की तरफ से भी अच्छी खबर मिलेगी। अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि कुछ समय से शारीरिक परेशानी की वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है।

मिथुन राशि- किसी खास प्रोजेक्ट पर निवेश करना बहुत फायदेमंद रहेगा और भविष्य में भी इसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। इसलिए मौके को हाथ से जाने न दें। उलझन की स्थिति में घर के अनुभवी सदस्य की सलाह लेना भी सही रहेगा। कुछ विरोधी जलन की भावना से आपके खिलाफ अफवाहें फैला सकते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा।

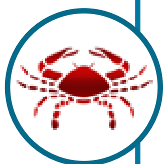

कर्क राशि- किसी निजी योजना पर काम करने का अच्छा समय है। आपका इरादा पूरा होगा। किस्मत आपका साथ दे रही है। कोई महत्वपूर्ण खबर मिलेगी और आप भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे। कहीं भी बातचीत करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। अपने खास मित्र की परेशानियों को ध्यान से सुनें और सुलझाने की भी कोशिश करें।

सिंह राशि- सितारों की स्थिति अच्छी है। सोच-समझकर किया गया कोई भी काम आगे चलकर फायदा देगा। संतान की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। सांसारिक कामों को भी आप बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। अपनी निजी बातें किसी के साथ भी न बताएं, वरना बिना मतलब किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं।

कन्या राशि- कोई महत्वपूर्ण सफलता आपका इंतजार कर रही है, इसलिए आलस और लापरवाही छोड़कर अपने कामों पर ध्यान दें। सकर महिलाओं के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या सम्मेलन में सफलता मिलने के योग हैं। ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर लिया गया फैसला गलत साबित हो सकता है। भाग्यशाली अंक- 7

तुला राशि- प्रॉपर्टी या गाड़ी से संबंधित लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो जलद आपकी परेशानी हल हो सकती है। यह समय परिवार के साथ आराम और मौज-मस्ती में बीतेगा। घर के बदलाव से जुड़ी योजनाएं सच हो सकती हैं। पुश्तैनी संपत्ति या किसी बात को लेकर भाइयों से बहस होने की संभावना है, लेकिन सावधानी और समझदारी से हालात ठीक भी हो जाएंगे।

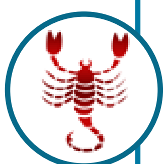

वृश्चिक राशि- कोई अच्छी खबर मिलने से खुश और उत्साहित महसूस करेंगे। व्यस्त रहने के बावजूद आप सामाजिक या आध्यात्मिक कामों के लिए भी समय निकाल लेंगे। पिछले कुछ समय से किसी करीबी रिश्तेदार के साथ चल रहे झगड़े भी हल होंगे। बहुत ज्यादा मेहनत के बावजूद बनते कामों में कुछ रुकावट आने से परेशानियां बढ़ेंगी।

धनु राशि- परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं, जो कि सही रहेंगे। किसी मित्र का सहयोग भी आपकी दिक्कतों को कम करने में मदद करेगा। कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सुधार होने से दिनचर्या व्यवस्थित हो जाएगी। किसी करीबी रिश्तेदार के साथ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है।

मकर राशि- परेशानियों से घबराने की बजाय उनका हल ढूंढने की कोशिश करें, तो सफलता जरूर मिलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। घर की देखरेख और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय बीतेगा। बच्चों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखना जरूरी है। कोई भी फैसला लेने से पहले उसपर अच्छे से सोच-विचार जरूर करें।

कुंभ राशि- अपने रुके हुए निजी कामों को निपटाने का अच्छा समय है। व्यस्त रहने के बावजूद घर-परिवार और सगे-संबंधियों के लिए भी समय निकाल लेंगे। युवाओं को अपने किसी विशेष काम को लेकर लोगों से तारीफ मिलेगी और उनके आत्मविश्वास में भी निखार आएगा। अनजान लोगों से लेन-देन में सावधानी बरतें। आप किसी साजिश का शिकार भी हो सकते हैं।

मीन राशि- प्रभावशाली लोगों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। कोई भी फैसला भावनाओं में आकर न लें, सोच-समझकर फैसला लेने से आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिना वजह के खर्चों पर रोक लगाएं। अपने गुस्से और नकारात्मक शब्दों के इस्तेमाल से अपने लिए ही परेशानियां बढ़ा लेंगे। मेहनत के अनुसार अच्छा नतीजा न मिलने से मन थोड़ा दुखी रहेगा।

रामायण के टीजर ने मचा दिया हंगामा, कुछ ही घंटो में हासिल किए 30 लाख से ज्यादा व्यूज

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' का गुरुवार को टीजर रिलीज किया गया। डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये फिल्म रामायण बॉलीवुड इतिहास में सबसे बड़े बजट की फिल्म बन गई है और 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही वायरल हो गया है। इतना ही नहीं फिल्म का टीजर रिलीज होते ही चंद घंटों में ही छा गया है। टीजर ने महज 5 घंटे में ही 30 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। इतना ही नहीं अभी भी ये टीजर यूट्यूब पर छाया हुआ है। फिल्म की स्टारकास्ट का खुलासा हो गया है और रणबीर कपूर के लुक को भी लोगों ने देख लिया है। हालांकि ये फ़िल्म का टीजर कम इंट्रोडक्ट्री वीडियो ज्यादा लग रहा है।

रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायण' का गुरुवार को टीजर रिलीज किया गया। डायरेक्टर नितेश तिवारी की ये फिल्म रामायण बॉलीवुड इतिहास में सबसे बड़े बजट की फिल्म बन गई है और 1200 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। फिल्म का टीजर रिलीज होते ही वायरल हो गया है। इतना ही नहीं फिल्म का टीजर रिलीज होते ही चंद घंटों में ही छा गया है। टीजर ने महज 5 घंटे में ही 30 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। इतना ही नहीं अभी भी ये टीजर यूटयूब पर छाया हुआ है। फिल्म की स्टारकास्ट का खुलासा हो गया है और रणबीर कपूर के लुक को भी लोगों ने देख लिया है। हालांकि ये फिल्म का टीजर कम इंट्रोडक्ट्री वीडियो ज्यादा लग रहा है।

3 मिनट के टीजर में दिखी कहानी की झलक

भारत में रामायण उन महाकाव्यों में से एक है जिसकी कहानियों ने सदियों तक समाज को सभ्य बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही हिंदु धर्म की आस्था में भी गहरी जगह बनाई है। रामायण की कहानी को टीवी पर भी दिखाया जा चुका है और बीते दिनों प्रभास स्टारर फिल्म आदिपुरुष भी रामायण पर ही बनी थी। लेकिन अब पहली बार रामायण की कहानी को अलग तरह से पेश किया गया है। फिल्म के टीजर में रामायण के पहले और परे की कहानी को भी दिखाने का प्रयास किया है। फिल्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शनिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया है। टीजर में दमदार और धाकड़ एक्टर यश का भी रावण लुक सामने आया है। इस लुक में यश खूब जम रहे हैं। इसके साथ ही रणबीर कपूर ने भी राम के किरदार में कमाल किया है।

साई पल्लवि ने निभाया सीता का किरदार

बता दें कि साउथ सुपरस्टार साई पल्लवि ने फिल्म में सीता का किरदार निभाया है। इसके साथ ही सनी देओल भी हनुमान के रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म 2 पाट्र्स में बनाई जा रही है और इसका एक भाग अगले साल 2026 की दीपावली पर रिलीज किया जाना है। इसका एक और भाग अगले साल 2027 की दीपावली पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में 4 ऑस्कर जीत चुके म्यूजिक आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और 8 ऑस्कर अवॉर्ड जीत चुकीं वीएफएक्स कंपनियां भी काम कर रही हैं। ये फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़े बजट की फिल्म बन गई है।

कैसी रही रामायण की 'सीता' की अब तक की करियर जर्नी?

साई पल्लवी का जन्म तमिलनाडू में 9 मई 1992 को हुआ था। एक्ट्रेस ने अपनी स्कूलिंग कोयंबटूर के अवीला कॉन्वेंट स्कूल से की थी। इसके बाद साई पल्लवी जॉर्जिया की तिब्लिसि स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन भी दिया। साई पल्लवि ने बतौर हीरोइन साल 2015 में फिल्म 'प्रेमम' के जरिए अपने किरयर की शुरुआत की थी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी और बिना प्रमोशन के चुपचाप सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साई पल्लवी एक साउथ सिनेमा की उभरती हुई हीरोइन बन गई। इस रोल के लिए पल्लवी को बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का साउथ फिल्म फेयर अवॉर्ड भी मिला। इसके बाद साई पल्लवि ने साल 2016 में काली फिल्म में दुलकर सलमान के साथ लीड रोल निभाया और सुपरहिट रहीं। इसके बाद साई पल्लवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब तक 15 फिल्में कर डाली हैं।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

USACS

NACO
National AIDS Control Organisation

जब नशा करे परेशान, OST ही है समाधान !

ओ.एस.टी. लेने के फायदे

- नशे की लत से मुक्ति
- सुई की आदत से छुटकारा
- एच. आई. वी. से पूर्णतः सुरक्षा

OST संपूर्ण सुरक्षा केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध हैं

AIDS Helpline 1097

अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें
परामर्श और सेवाओं के लिए संपूर्ण सुरक्षा केंद्र जाएँ

SAMPOORNA SURAKSHA

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
दूरभाष: 0135-2608885, ई-मेल: uksacs1@gmail.com, वेबसाईट: www.usacs.org.in

उत्तराखण्ड राज्य एड्स नियंत्रण समिति, देहरादून द्वारा जनहित में जारी।